

अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार



चिकित्सीय आपातकाल/एम्बुलेंस सेवा के लिए कृपया 112 पर डायल करें।

रजि.न.34300/80 | संख्या 289 | श्री विजय पुरम, गुरूवार, 29 अक्टूबर 2026 | web: dt.andamannicobar.gov.in | 2.00 रूपए





माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वाहन पर अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा जी ने लोक निवास, श्री विजय पुरम से "टीबी मुक्त भारत" पहल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सभी कर्मचारियों को 'टीबी मुक्त भारत' की शपथ दिलाई गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस पहल के तहत लोक निवास के सभी कर्मचारियों की स्वास्थ्य स्क्रीनिंग कर अभियान प्रारम्भ किया गया।

इस अवसर पर आयुक्त–सह–सचिव (स्वास्थ्य), सचिव (स्वास्थ्य) व अन्य अधिकारीगण एवं लोक निवास के कर्मचारी उपस्थित रहे।



अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा जी से आज लोक निवास, श्री विजय पुरम, में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी ने शिष्टाचार भेंट की।





अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा जी ने आज लोक निवास, श्री विजय पुरम, में समस्त विभागों की समीक्षा बैठक में पूर्व में दिए गए कार्यों की प्रगति आख्या से अवगत होकर कार्यों का निस्तारण शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

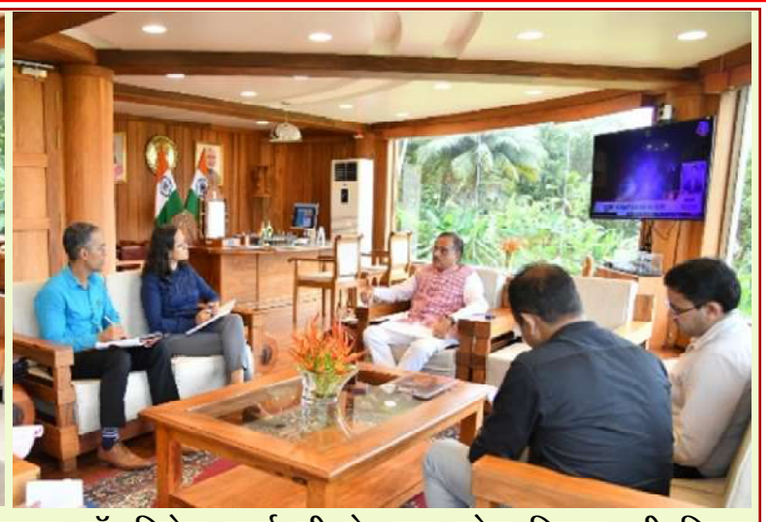
इस अवसर मुख्य सचिव श्री ज्ञानेश भारती, पुलिस महानिदेशक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं समस्त विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।





अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा जी ने आज लोक निवास, श्री विजय पुरम, में सचिव उप राज्यपाल सचिवालय, विशेष सचिव, विशेष कार्य अधिकारी एवं लोक निवास में कार्यरत अन्य कर्मचारियों के साथ बैठक कर विभिन्न दिशा–निर्देशों के अनुपालन को निर्धारित समय–सीमा में सुनिश्चित करने तथा आगामी 'जनता दर्शन' कार्यक्रम के सुव्यवस्थित एवं सफल आयोजन के लिए आवश्यक निर्देश देकर कार्यों का वितरण किया।





अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा जी ने आज लोक निवास, श्री विजय पुरम, में बैठक कर दीपावली के मद्देनज़र बाज़ार में आतिशबाजी एवं खाद्य सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण बनाए रखने, निर्धारित दरों से अधिक मूल्य वसूलने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा संबंधित विभागों को नियमित निरीक्षण और व्यापारी संघों के साथ बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए। साथ ही, मिठाइयों में मिलावट की रोकथाम एवं खाद्य सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा।

सतर्कता अभियान एवं सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2026

'निवारक सतर्कता एवं क्षमता संवर्धन' पर कार्यशाला का आयोजन

दंडात्मक सतर्कता की अपेक्षा निवारक सतर्कता को अधिक प्राथमिकता देने पर बल

श्री विजय पुरम, 28 अक्टूबर।

भारत में प्रत्येक वर्ष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती वाले सप्ताह में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जागरूकता कार्यक्रमों एवं निवारक सतर्कता संबंधी पहलों के माध्यम से लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता तथा नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना है। इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2026 का आयोजन 26 अक्टूबर से 1 नवंबर, 2026 तक 'समृद्धि के लिए सत्यनिष्ठा' विषयवस्तु के अंतर्गत किया जा रहा है।





इसी क्रम में अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के सतर्कता विभाग द्वारा 28 अक्टूबर, 2026 को श्री विजय पुरम स्थित टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में प्रशासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए 'निवारक सतर्कता एवं क्षमता संवर्धन' विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य लोक सेवा में पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा, जवाबदेही एवं नैतिक आचरण को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दोहराना तथा प्रशासनिक व्यवस्था से भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए सामूहिक प्रयासों को और अधिक सुदृढ़ करना था। इस कार्यशाला के माध्यम से विभिन्न विभागों के जांच प्राधिकारियों, प्रस्तुतीकरण अधिकारियों तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्कता संबंधी मामलों एवं निवारक सतर्कता के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण प्रदान करने और उनकी कार्यक्षमता एवं दक्षता में वृद्धि करने पर विशेष बल दिया गया। कार्यशाला का उद्घाटन अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव–सह–मुख्य सतर्कता अधिकारी, श्री ज्ञानेश भारती, भा.प्र.से., द्वारा किया गया। इस कार्यशाला में लगभग 200 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव श्री ज्ञानेश भारती ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए दंडात्मक सतर्कता की अपेक्षा निवारक सतर्कता को अधिक प्राथमिकता देने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि

शेष पृष्ठ 4 पर

'संपर्क से समाधान प्रशासन गाँव की ओर' पहल

उपायुक्त, उत्तर व मध्य अण्डमान ने डिगलीपुर में आयोजित किया राजस्व शिविर–सह–जन शिकायत निवारण कार्यक्रम

मायाबंदर, 28 अक्टूबर।

'संपर्क से समाधान–प्रशासन गाँव की ओर' पहल के अंतर्गत 28 अक्टूबर, 2026 को सहायक आयुक्त कार्यालय, डिगलीपुर में राजस्व शिविर–सह–जन शिकायत निवारण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तर व मध्य अण्डमान ज़िले के उपायुक्त श्री सुशांत पधा, भा.प्र.से., के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में सहायक आयुक्त, डिगलीपुर भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के प्रतिनिधियों, विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारियों तथा आम जनता ने भाग लिया।



कार्यक्रम के दौरान पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों ने कृषि, विद्युत आपूर्ति, सड़क संपर्क, जल निकासी, परिवहन, जनसुविधाओं तथा भूमि संबंधी विभिन्न समस्याओं को उठाया। उपायुक्त ने लोगों की शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुना तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ विचार–विमर्श किया। उन्होंने जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने, शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा निर्धारित समय–सीमा के भीतर शिकायतों का निवारण करने पर विशेष बल दिया।

राजस्व शिविर–सह–न्यायालय के अंतर्गत भूमि उप–विभाजन, नाम में सुधार तथा भूमि नामांतरण से संबंधित मामलों की सुनवाई की गई। इनमें से संबंधित मामलों का निपटारा मौके पर ही किया गया। इससे राजस्व संबंधी मामलों के त्वरित निस्तारण में सहायता मिली तथा आवेदकों को तत्काल राहत प्राप्त हुई।

शेष पृष्ठ 4 पर

'निवारक सतर्कता एवं क्षमता संवर्धन' पर

—————————पृष्ठ 1 का शेष

भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है जनता और प्रशासन के बीच प्रत्यक्ष संपर्क की आवश्यकता को न्यूनतम करना तथा सरकारी विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं एवं योजनाओं को ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराना। साथ ही, इन सेवाओं की निगरानी निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ तरीके से की जानी चाहिए। इसके लिए सेवाएँ प्रदान करने में लगने वाले समय तथा सेवा वितरण से संबंधित मानकों का विश्लेषण करना आवश्यक है।

उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि वह अपने आधिकारिक दायित्वों का निर्वहन निर्धारित समय–सीमा के भीतर पूर्ण सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ करे। मुख्य सचिव ने सतत एवं प्रभावी सुशासन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भारत सरकार की विभिन्न प्रक्रियाओं, नियमों, निर्देशों तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशा–निर्देशों से नियमित रूप से अवगत रहने और अपनी कार्यप्रणाली को समयानुकूल बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने कार्यशाला में भाग लेने वाले जांच अधिकारियों एवं प्रस्तुतीकरण अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे लंबित विभागीय जांचों को निर्धारित समय–सीमा के भीतर पूरा करें, ताकि मामलों का शीघ्र निस्तारण हो सके और समय पर निर्णय लिए जा सकें। उन्होंने लंबित मामलों के निपटान के लिए मिशन मोड में कार्य करने का भी आह्वान किया।

मुख्य सचिव ने निवारक सतर्कता की संस्कृति को बढ़ावा देने पर ज़ोर देते हुए कहा कि सतर्कता की वास्तविक सफलता केवल भ्रष्टाचार होने के बाद उसकी पहचान करने में नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्थाओं एवं कार्यप्रणालियों के निर्माण में निहित है, जो भ्रष्टाचार को प्रारंभिक स्तर पर ही रोकने में सक्षम हों।

उन्होंने प्रतिभागियों से सतर्कता के सक्रिय संवाहक बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों को न केवल स्वयं नियमों एवं निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुरूप कार्य करना चाहिए, बल्कि अपने–अपने कार्यक्षेत्रों में नैतिक आचरण को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके साथ ही, उन्हें अपने सहकर्मियों एवं अन्य कर्मचारियों को निवारक सतर्कता, सत्यनिष्ठा और जवाबदेही के महत्व के प्रति जागरूक करना चाहिए।

इस अवसर पर सतर्कता विभाग के आयुक्त–सह–सचिव, डॉ. सचिन शिंदे ने अपने संबोधन में नए एवं परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण विकसित करने तथा प्रशासनिक व्यवस्था में विद्यमान कमियों की निरंतर पहचान कर उन्हें दूर करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सतर्कता संबंधी मामलों की जटिल प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए निरंतर सीखने एवं अपने ज्ञान को अद्यतन करते रहने की आवश्यकता है। इससे मामलों के तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर उचित निर्णय लेने में सहायता मिलेगी तथा जांच प्रक्रिया को बिना किसी अनावश्यक उत्पीड़न और विलंब के पूरा किया जा सकेगा।

केंद्रीय सतर्कता आयोग के निदेशक, श्री धनंजय कुमार रंजन ने सतर्कता संबंधी शिकायतों में निहित पहलुओं, उन पर की जाने वाली अनुवर्ती कार्रवाई तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श एवं राय प्राप्त करने की आवश्यकता के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने प्रतिभागियों को विभिन्न प्रकार की शिकायतों के निस्तारण में अपनाए जाने वाले चरणों एवं प्रक्रियाओं से अवगत कराया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सूचना उजागर करने वाले व्यक्तियों (व्हिसलब्लोअर्स) के संरक्षण तथा जनहित में सूचना प्रकटीकरण एवं सूचना देने वालों के संरक्षण से संबंधित प्रावधानों की भी जानकारी दी।

कार्यशाला के दौरान भ्रष्टाचार–निवारण इकाई द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मामलों से संबंधित प्रक्रियात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2018 की धारा 17 एवं 19 के अंतर्गत जांच की अनुमति तथा अभियोजन की स्वीकृति से संबंधित प्रावधानों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

कार्यशाला में निवारक सतर्कता से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी संवादात्मक सत्र आयोजित किए गए। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से किए जाने वाले हस्तक्षेप एवं पहल, आरोप–पत्र तैयार करने की प्रक्रिया, विभागीय जांच में जांच अधिकारियों एवं प्रस्तुतीकरण अधिकारियों की भूमिका तथा सतर्कता अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने से संबंधित विषय शामिल थे।

इन सत्रों का संचालन विभिन्न विषय–विशेषज्ञों एवं सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों सहित अन्य संसाधन व्यक्तियों द्वारा किया गया। कार्यशाला में विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और विषयों पर सक्रिय संवाद किया। कार्यशाला का समापन इसमें शामिल विषयों पर आधारित प्रश्नोत्तरी के साथ हुआ।

संयुक्त सचिव (सतर्कता) से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों ने अपने आधिकारिक दायित्वों का निर्वहन करते समय सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, कार्यकुशलता एवं जवाबदेही के उच्च मानकों को बनाए रखने तथा लोक सेवा में नैतिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

उपायुक्त, उत्तर व मध्य अण्डमान ने डिगलीपुर में

—————————पृष्ठ 1 का शेष

इस कार्यक्रम में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शिविर में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, विभिन्न कार्यालयों के प्रमुखों, विभागीय अधिकारियों–कर्मचारियों तथा आम जनता सहित लगभग 350 लोग उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में लोगों की सहभागिता ने इस पहल के प्रति जनभागीदारी में बढ़ती रुचि को प्रदर्शित किया। साथ ही, यह कार्यक्रम प्रशासनिक सेवाओं को आम जनता के और अधिक निकट पहुँचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।



प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इस राजस्व शिविर–सह–जन शिकायत निवारण कार्यक्रम ने सुलभ, पारदर्शी एवं नागरिक–केंद्रित प्रशासन सुनिश्चित करने के प्रति ज़िला प्रशासन की प्रतिबद्धता को पुनः सुदृढ़ किया। 'संपर्क से समाधान–प्रशासन गाँव की ओर' पहल के माध्यम से ज़िला प्रशासन नागरिकों के साथ सीधे संवाद को बढ़ावा देने, स्थानीय स्तर पर जनसमस्याओं का समाधान करने तथा सार्वजनिक सेवाओं की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस पहल का उद्देश्य आम नागरिकों की शिकायतों का प्रभावी निवारण करते हुए प्रशासनिक सेवाओं को जनसामान्य तक सुगमता से पहुँचाना है।

पर्णशाला में सामुदायिक मसाला उद्यान की स्थापना हेतु दालचीनी के पौधों का रोपण

रंगत, 28 अक्टूबर।

कृषि विभाग ने ग्राम पंचायत पर्णशाला, रंगत, मध्य अण्डमान के सहयोग से आज पर्णशाला स्थित सामुदायिक मसाला उद्यान स्थल पर दालचीनी के पौधों का रोपण किया। यह पहल पीएम–आरकेवीवाई योजना तथा मसाला प्रवाह मिशन के अंतर्गत सामुदायिक मसाला उद्यानों की स्थापना के तहत की गई। इस अवसर पर सहायक आयुक्त, रंगत श्री दीपांशु वोहरा, तहसीलदार श्री कैस्पर जेम्स, ग्राम पंचायत पर्णशाला के प्रधान श्री बालमुरुगन सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने कृषि विभाग की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे मसालों की खेती का विस्तार करने, किसानों की आजीविका को सुदृढ़ बनाने तथा द्वीपों में टिकाऊ कृषि विकास को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएं हैं। इस परियोजना के अंतर्गत रंगत क्षेत्र में कुल 40 हेक्टेयर भूमि को शामिल किया गया है। इसमें पांच ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 30 हेक्टेयर भूमि पर पौधरोपण किया जाएगा। इनमें बकुलतला में 11 हेक्टेयर, नींबूतला में 7 हेक्टेयर, कौशल्यानगर में 7 हेक्टेयर, उत्तरा में 3 हेक्टेयर तथा पर्णशाला में 2 हेक्टेयर भूमि शामिल है। इसके अतिरिक्त, सीपी चित्रकूट स्थित विभागीय फार्म



में 10 हेक्टेयर भूमि पर भी पौधरोपण किया जाएगा।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार यह परियोजना 5 अक्टूबर को प्रारंभ हुई थी। इसके अंतर्गत दिसंबर 2026 के अंत तक दालचीनी के कुल 1,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कृषि विभाग, पंचायतों तथा कृषक समुदाय के बीच समन्वित प्रयासों के माध्यम से इस परियोजना का उद्देश्य टिकाऊ मसाला खेती के लिए मजबूत आधार तैयार करना, किसानों की आय में वृद्धि करना तथा द्वीपों में दीर्घकालिक स्तर पर मसाला उत्पादन का विस्तार करना है।

बकुलतला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में हुआ युवा संवाद कार्यक्रम

रंगत, 28 अक्टूबर।

युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत मेरा युवा भारत, रंगत, उत्तर व मध्य अण्डमान ज़िले द्वारा आज बकुलतला स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 200 से अधिक विद्यार्थियों एवं युवा नागरिकों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम देशभर के 500 विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों में 26 अक्टूबर से 5 नवंबर, 2026 तक आयोजित किए जा रहे राष्ट्रव्यापी विकसित भारत युवा संवाद अभियान के अंतर्गत आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत बकुलतला के प्रधान श्री नारायण मंडल ने सहभागिता की। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण विद्यार्थियों और उत्तर व मध्य अण्डमान के



युवा प्रेरणास्रोत श्री देबोजीत हलदर के बीच आयोजित संवादात्मक चर्चा रही। कार्यक्रम का समापन लोकतांत्रिक शपथ के साथ हुआ।

पंचायतों एवं नगरपालिका परिषद के आम चुनावों के लिए मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित

श्री विजय पुरम, 28 अक्टूबर।

केंद्रशासित प्रदेशों के निर्वाचन आयुक्त ने संविधान के अनुच्छेद 243–के एवं 243–ज़ेडए, तथा अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (पंचायत) विनियम, 1994 की धारा 185 और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (नगरपालिका) विनियम, 1994 की धारा 32 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी पंचायतों एवं नगरपालिका परिषद के आम चुनावों के लिए मतदाता सूचियों के अद्यतन एवं पुनरीक्षण की प्रक्रिया निर्धारित की है।

इसके तहत अगस्त 2025 में संशोधित एवं अद्यतन की गई पंचायतों तथा नगरपालिका परिषद की अंतिम मतदाता सूचियों को आधार मतदाता सूची के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में निर्धारित कार्यक्रम निम्नलिखित है:

क्रम संख्या	गतिविधि	अवधि/तिथि
1.	प्रारूप मतदाता सूचियों की तैयारी	28 अक्टूबर 2026 (बुधवार) से 30 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार) तक
2.	प्रारूप मतदाता सूचियों का मुद्रण	31 अक्टूबर 2026 (शनिवार) से 2 नवंबर 2026 (सोमवार) तक
3.	प्रारूप मतदाता सूचियों का प्रकाशन	3 नवंबर 2026 (मंगलवार)
4.	सुझाव एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने की अवधि	3 नवंबर 2026 (मंगलवार) से 17 नवंबर 2026 (मंगलवार) तक
5.	सुझावों एवं आपत्तियों का निपटारा	19 नवंबर 2026 (गुरुवार) तक
6.	मतदाता सूचियों की तैयारी एवं मुद्रण	20 नवंबर 2026 (शुक्रवार) से 23 नवंबर 2026 (सोमवार) तक
7.	अंतिम मतदाता सूचियों का प्रकाशन	24 नवंबर 2026 (मंगलवार)

जेएनआरएम की प्राध्यापिका डॉ. मुक्ता जगदीश को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मिली मान्यता

श्री विजय पुरम, 28 अक्टूबर।



जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय (जेएनआरएम), श्री विजय पुरम के कंप्यूटर विज्ञान विभाग की सहायक प्राध्यापिका डॉ. मुक्ता जगदीश ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त एक कीर्तिमान में सहभागिता कर महाविद्यालय एवं अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह को गौरवान्वित किया है। उन्होंने 26 जुलाई, 2026 को तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के कीर्तिमान "एक साथ अपनी पुस्तक पर हस्ताक्षर करने वाले सर्वाधिक लेखक" में भाग लिया। इस आयोजन का संचालन भारत के ईएसएन पब्लिकेशंस ने ब्रिटेन के लंदन ऑर्गनाइजेशन ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट के सहयोग से किया, जिसमें कुल 1,572 लेखकों ने भाग लिया।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार यह उपलब्धि उनके व्यावसायिक जीवन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है तथा लेखन और ज्ञान–साझाकरण के क्षेत्र में उनके योगदान को मान्यता प्रदान करती है। जेएनआरएम की प्राचार्या डॉ. पर्ल देवदास ने महाविद्यालय के प्राध्यापकों एवं समस्त कर्मचारियों के साथ डॉ. मुक्ता जगदीश को इस उपलब्धि पर बधाई दी तथा उनके सफल प्रयास पर गर्व व्यक्त किया। उनकी इस उपलब्धि से जेएनआरएम और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह को गौरव प्राप्त हुआ है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2026 : मोटरसाइकिल रैली निकाली गई





श्री विजय पुरम, 28 अक्टूबर।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2026 के आयोजन के अंतर्गत, अण्डमान तथा निकोबार पुलिस द्वारा 26 अक्टूबर, 2026 को ईमानदारी, पारदर्शिता तथा भ्रष्टाचार की रोकथाम के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता) श्रीमती गीता रानी वर्मा, भा.पु.से. ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक (भ्रष्टाचार निवारण इकाई/सतर्कता) श्री मनीष कुमार, उप पुलिस अधीक्षक (सतर्कता/मुख्यालय) श्रीमती सुम्मा मड्डा, विभागीय कर्मचारी तथा अन्य प्रतिभागी उपस्थित थे। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार रैली ने घंटा घर, सेल्यूलर जेल, मरीना पार्क एवं फ्लैग प्वाइंट जैसे प्रमुख स्थलों से गुजरते हुए सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, जवाबदेही और नैतिक आचरण का संदेश दिया। इस पहल का उद्देश्य आम जनता को भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष के महत्व के प्रति जागरूक करना तथा नागरिकों को अपने व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक जीवन में ईमानदारी बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना था। कार्यक्रम का समापन सभी नागरिकों से सतर्क रहने, भ्रष्ट आचरण की सूचना देने तथा सुशासन को बढ़ावा देने में अपना योगदान देने की अपील के साथ हुआ।

जेएनआरएम में मनाया जा रहा है सतर्कता जागरूकता सप्ताह

श्री विजय पुरम, 28 अक्टूबर।



जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय (जेएनआरएम), श्री विजय पुरम ने "सत्यनिष्ठा से समृद्धि" विषय के अंतर्गत सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2026 के आयोजन में भाग लिया। इस अवसर पर सत्यनिष्ठा की शपथ ग्रहण समारोह तथा नैतिक आचरण को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार से मुकाबला करने के उद्देश्य से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

सप्ताहव्यापी आयोजन का उद्देश्य भ्रष्टाचार के विभिन्न स्वरूपों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना तथा पारदर्शी एवं जवाबदेह समाज के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों के लिए जागरूकता व्याख्यान, निबंध एवं पोस्टर प्रतियोगिताएँ, वाद–विवाद तथा नैतिकता और सुशासन से संबंधित परिचर्चाओं सहित विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित करने की योजना बनाई गई है। जेएनआरएम के सभी विभागों में संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा विद्यार्थियों को सतर्कता की शपथ दिलाई गई। 26 अक्टूबर को आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम के अंतर्गत महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. पर्ल देवदास ने प्राध्यापकों, मंत्रालयिक एवं लिपिकीय कर्मचारियों तथा संस्थान से जुड़े अन्य हितधारकों को सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शपथ दिलाई। इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों ने अपने व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत जीवन में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इस अवसर पर डॉ. पर्ल देवदास ने सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी एवं नैतिक मूल्यों के महत्व पर ज़ोर दिया तथा विद्यार्थियों और कर्मचारियों से भ्रष्टाचार–मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। यह आयोजन शैक्षणिक समुदाय में सत्यनिष्ठा और ज़िम्मेदार नागरिकता की भावना विकसित करने तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध राष्ट्रीय अभियान को समर्थन देने के प्रति जेएनआरएम की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

अंतरविद्यालयी रस्सी कूद प्रतियोगिता में 300 विद्यार्थियों ने लिया भाग

श्री विजय पुरम, 28 अक्टूबर।

उप शिक्षा कार्यालय, दक्षिण अण्डमान के खेल अनुभाग द्वारा आज राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के सभागार में बालक एवं बालिकाओं के लिए अंतरविद्यालयी रस्सी कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में उप शिक्षा कार्यालय, दक्षिण अण्डमान के अधिकार क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के लगभग 300 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के परिणाम इस प्रकार रहे: पहली से पांचवीं तक के बालक वर्ग में आरबीवी के हसनुर गाज़ी, स्वराज द्वीप के कृष्णानगर स्कूल के जॉय केरकेट्टा, हम्फ्रीगंज स्कूल के रमन महतो को क्रमशः पहला तीन स्थान स्थान प्राप्त हुआ, वहीं बालिका वर्ग में आरबीवी की शेफाली मंडल, डॉलीगंज स्कूल की दीपिका बागे को प्रथम, मरियम्मन मंदिर स्कूल की दर्पण पटनायक, स्वराज द्वीप के कृष्णानगर स्कूल की सोहाना बिश्वास को द्वितीय, एनसीएस की कशिका एन. तावकर को तृतीय स्थान मिला। छठवीं से दसवीं तक के बालक वर्ग में बालक विद्यालय के तबरेज़, स्वराज द्वीप के कृष्णानगर स्कूल के देबाजीत सिल, स्वराज द्वीप के कृष्णानगर स्कूल के दीपांगशू सिल को क्रमशः पहला तीन स्थान मिला। बालिका वर्ग में एनसीएस की



आरोही, वीकेवी की लक्ष्मिता तथा भातू बस्ती स्कूल की रीता सरदार को क्रमशः प्रथम तीन स्थान प्राप्त हुआ।

कनिष्ठ अभियंता परीक्षा–2026

श्री विजय पुरम, 28 अक्टूबर।

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कनिष्ठ अभियंता परीक्षा–2026 पर्चा–1 का आयोजन 2 नवंबर से 6 नवंबर, 2026 तक किया जाएगा। उप सचिव (आरएंडई) की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के ई–प्रवेश पत्र निर्धारित परीक्षा तिथि से 3–4 दिन पहले आयोग की वेबसाइटों (https://ssc.gov.in/ |https://sscer.org/) पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन–229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) पी. कैरल डी. सोणी
e-mail:dweepsamachar@gmail.com

2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य, भारत बनेगा स्वच्छ ऊर्जा का वैश्विक केंद्र

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत ने 2030 तक प्रतिवर्ष 50 लाख मीट्रिक टन (5 एमएमटी) ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। बुधवार को जारी एक आधिकारिक फैक्टशीट के अनुसार, यह पहल देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने और भारत को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

सरकार का मानना है कि राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भारत को अधिक स्वच्छ, आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी ऊर्जा अर्थव्यवस्था बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। मिशन के तहत वर्ष 2030 तक जीवाश्म ईंधन आयात पर होने वाले कुल खर्च में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की बचत का अनुमान है।

इस मिशन का उद्देश्य केवल ऊर्जा सुरक्षा बयाना नहीं, बल्कि औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार सृजन को भी नई गति देना है। सरकार का अनुमान है कि इस पहल से 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित होगा और विनिर्माण, बुनियादी ढांचा, अनुसंधान तथा परियोजना विकास जैसे क्षेत्रों में 6 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

फैक्टशीट में कहा गया है कि मिशन के तहत निर्धारित मात्रा में ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन और उपयोग होने से हर वर्ष लगभग 5 करोड़ टन (50 एमएमटी) कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोका जा सकेगा। इससे भारत के जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने में उल्लेखनीय मदद मिलेगी।

ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र को बयावा देने के लिए छह राज्यों ने पहले ही समर्पित नीतियां अधिसूचित कर दी हैं। इनमें गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, बिहार और केरल अपनी–अपनी ग्रीन हाइड्रोजन नीतियों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं।

वहीं हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और छत्तीसगय जैसे राज्यों ने ग्रीन हाइड्रोजन को अपनी मौजूदा औद्योगिक और नवीकरणीय ऊर्जा नीतियों में शामिल किया है।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग के मोर्चे पर भी भारत तेजी से आगे बय रहा है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, सऊदी अरब, यूएई और उज्बेकिस्तान के साथ विभिन्न समझौते, आशय–पत्र और संयुक्त घोषणाएं की हैं। इसके अलावा नीदरलैंड्स के साथ नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) भी हस्ताक्षरित किया गया है।

भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार को यूएई ने दिया 'ऑर्डर ऑफ जायद II' सम्मान

अबू धाबी, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। फ्लाईदुबई फ्लाइट को हाइजैक होने से बचाने के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने मच्छार समेत विमान के अन्य चालक दल सदस्यों को प्रथम श्रेणी के 'ऑर्डर ऑफ जायद II' से सम्मानित किया है।

दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने चालक दल को यह सम्मान प्रदान किया। दुबई मीडिया ऑफिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी दी। यूएई के नेतृत्व ने चालक दल की त्वरित कार्रवाई, जिम्मेदारी और व्यावसायिक दक्षता की सराहना करते हुए कहा, "यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना देश की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। राष्ट्रपति ने चालक दल के सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान यूएई के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।"

यह सम्मान 30 सितंबर को फ्लाईदुबई की उड़ान एफजेड1073 में हुई घटना के बाद दिया गया है। दुबई से तेल अवीव जा रहे विमान के कॉकपिट में सह–पायलट ने कैप्टन मच्छार पर हमला कर दिया था और विमान का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की कोशिश की थी। यूएई के अभियोजकों की जांच के अनुसार, आरोपी की मंशा विमान को इजरायल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त कर बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान पहुंचाने की थी।



गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन मच्छार ने कॉकपिट का दरवाजा खोलने में सफलता हासिल की। इसके बाद चालक दल के अन्य सदस्यों और यात्रियों ने हस्तक्षेप कर हमलावर को काबू में किया। विमान को सऊदी अरब के तबुक हवाई अड्डे की ओर मोड़ा गया, जहां उसे सुरक्षित उतारा गया। इस घटना में विमान में सवार यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की जान बच गई।

घटना के बाद शेख हमदान ने अस्पताल में कैप्टन मच्छार से मुलाकात कर उनके साहस और मानव जीवन की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना की थी। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी उनकी बहादुरी की प्रशंसा की थी। इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने भी कैप्टन मच्छर को स्वस्थ होने के बाद देश के नागरिक वीरता सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है।

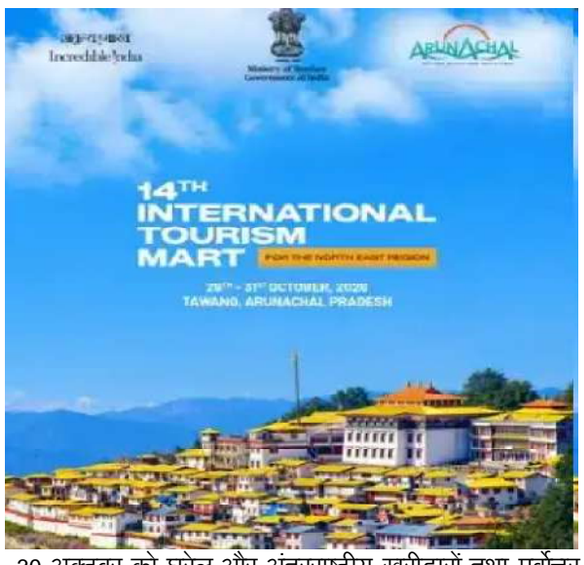
तवांग में आज से शुरू होगा 14वां अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट, 22 देशों के 43 खरीदार होंगे शामिल

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर (हि.स.)। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 29 से 31 अक्टूबर तक 14वां अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से आयोजित इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में पूर्वोत्तर क्षेत्र की पर्यटन संभावनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों तथा विक्रेताओं सहित 200 से अधिक प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है। अंतरराष्ट्रीय खरीदार 22 देशों का प्रतिनिधित्व करेंगे।

पर्यटन मंत्रालय अरुणाचल प्रदेश सरकार और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। 29 अक्टूबर को उद्घाटन समारोह में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पर्यटन और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी तथा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू शामिल होंगे। इस दौरान नॉर्थ ईस्ट बाजार का उद्घाटन और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

मंत्रालय के अनुसार, मार्ट में ऑस्ट्रेलिया, भूटान, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मलेशिया, फिलीपींस, पोलैंड, रूस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और अमेरिका सहित 22 देशों के 43 अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के भाग लेने की उम्मीद है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के आठ राज्यों के घरेलू खरीदार, पर्यटन सेवा प्रदाता और विक्रेता भी शामिल होंगे।

कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के पर्यटन स्थलों तथा उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें इन राज्यों के प्रमुख आकर्षणों, पर्यटन अनुभवों और संयुक्त पर्यटन सर्किट की जानकारी दी जाएगी।



30 अक्टूबर को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों तथा पूर्वोत्तर के पर्यटन सेवा प्रदाताओं के बीच कारोबार से जुड़ी बैठकें होंगी। इन बैठकों का उद्देश्य पर्यटन कारोबार में सहयोग बढ़ाना, नए पर्यटन उत्पाद विकसित करना और क्षेत्र के उद्यमियों को बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराना है।

मार्ट में पूर्वोत्तर में लाइव कार्यक्रमों और संगीत समारोहों से जुड़ी अर्थव्यवस्था तथा संरक्षित और प्रतिबंधित क्षेत्रों में पर्यटकों की पहुंच जैसे विषयों पर तकनीकी सत्र भी होंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय लाइव कार्यक्रमों और संगीत समारोहों से जुड़े सत्र का नेतृत्व करेगा, जबकि गृह मंत्रालय संरक्षित और प्रतिबंधित क्षेत्रों में पर्यटकों की पहुंच के विषय पर सत्र का नेतृत्व करेगा। रॉयल एनफील्ड की ओर से पूर्वोत्तर में अनुभव आधारित पर्यटन पर प्रस्तुति भी दी जाएगी।

मलेरिया वैक्सीन की कीमत में 40 फीसदी की कटौती, 10 लाख और बच्चों को मिलेगा सुरक्षा कवच

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर। मलेरिया के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूती देने के लिए भारत बायोटेक ने गावी और यूनिसेफ के साथ मलेरिया वैक्सीन की कीमत घटाने का समझौता किया है। इसके तहत वैक्सीन की कीमत करीब 40 फीसदी कम होगी। इससे 2027 से 2029 के बीच टीकाकरण कार्यक्रमों को करीब 5 करोड़ डॉलर की बचत होने और 10 लाख अतिरिक्त बच्चों को वैक्सीन की पूरी खुराक देने में मदद मिलेगी।

इस वैक्सीन को मूल रूप से जीएसके ने विकसित किया था। समझौते के तहत इसकी कीमत घटाकर 5.50 यूरो प्रति खुराक की जाएगी। नई कीमत 2027 की शुरुआत तक लागू होने की उम्मीद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2021 में इस वैक्सीन की सिफारिश की थी। वैक्सीन की चार खुराक का पूरा कोर्स मौसमी मलेरिया के अधिक प्रसार वाले क्षेत्रों में मलेरिया के मामलों को करीब 75 फीसदी तक कम कर सकता है।

भारत बायोटेक के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. कृष्णा एला ने कहा कि कंपनी ने वैक्सीन की उत्पादन क्षमता बयाने और इसकी आपूर्ति मजबूत करने में महत्वपूर्ण निवेश किया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक साझेदारों के साथ मिलकर कंपनी का लक्ष्य मलेरिया वैक्सीन को अधिक किफायती बनाना और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाना है।

गौरतलब है कि मलेरिया आज भी दुनिया भर में बच्चों के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। वर्ष 2024 में दुनियाभर में मलेरिया के करीब 28 करोड़ 20 लाख मामले सामने आए और लगभग 6 लाख 10 हजार लोगों की मौत हुई। इनमें से अधिकांश मामले और मौतें अफ्रीका में दर्ज की गईं।

कैबिनेट ने खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मंजूरी दी

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026 से 2033–34 की अवधि के लिए 1,856.67 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ 'खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम' को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य निवेश, विनिर्माण, नवाचार और निर्यात को बयावा देना और वैश्विक खेल सामग्री क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत करना है।

केंद्रीय बजट 2026–27 में घोषित यह योजना निवेश, तकनीक अपनाने, अनुसंधान और नवाचार, कौशल विकास, गुणवत्ता प्रमाणन और बाजार विकास के लिए लक्षित सहायता के माध्यम से भारत के खेल सामग्री निर्माण आधार को मजबूत करने का प्रयास करती है। यह योजना वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी खेल सामग्री उद्योग के विकास में मदद करेगी और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की स्थिति को मजबूत करेगी।

'खेलो भारत नीति 2025', 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' के विजन के अनुरूप, इस योजना से निवेश आकर्षित होने, रोजगार के अवसर पैदा होने, घरेलू विनिर्माण क्षमताओं के मजबूत होने और भारतीय खेल सामग्रियों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बयने की उम्मीद है।

इस योजना में समर्पित 'स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग जोन' (एसजीएमजेड) विकसित करने की परिकल्पना की गई है। इसका उद्देश्य क्लस्टर–आधारित विनिर्माण को बयावा देना और निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, परीक्षण सुविधाओं, डिजाइन और प्रोटोटाइपिंग केंद्रों तथा सहायक उद्यमों को एक ही स्थान पर लाकर एक एकीकृत औद्योगिक इकोसिस्टम तैयार करना है। इन जोन को 'भव्य' योजना और एनआईसीडीसी औद्योगिक पार्कों के तहत मौजूदा औद्योगिक बुनियादी ढांचे के साथ जोड़कर विकसित किया



जाएगा। इससे कुशल विनिर्माण, मजबूत औद्योगिक जुड़ाव और खेल सामग्री मूल्य श्रृंखला में बेहतर प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित होगी।

ये जोन एकीकृत विनिर्माण सुविधाओं के निर्माण में मदद करेंगे, औद्योगिक संबंधों को मजबूत करेंगे और परिचालन दक्षता में सुधार करेंगे। इन प्रयासों से निवेश को बयावा मिलने, उत्पादन क्षमता बयने और देश में एक मजबूत खेल सामग्री निर्माण आधार के विकास में मदद मिलने की उम्मीद है।

इस योजना का एक मुख्य फोकस खेल सामग्री क्षेत्र में नया निवेश आकर्षित करना और घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना है। 'एंकर इन्वेस्टमेंट सपोर्ट' घटक प्रमुख घरेलू और वैश्विक निर्माताओं, ब्रांड्स और रिटेल चेन को 'स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग जोन' (खेलकूद के सामान बनाने वाले क्षेत्र) में अपनी निर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। साथ ही, यह एक मजबूत आपूर्तिकर्ता और सहायक इकोसिस्टम के विकास को भी बयावा देगा। इसके पूरक के रूप में, 'टर्नओवर लिंक्ड सपोर्ट' घटक अधिक उत्पादन, क्षमता विस्तार और निरंतर विनिर्माण वृद्धि को बयावा देगा।

शिपिंग, जहाज निर्माण और समुद्री तकनीक में साझेदारी बढ़ाने की तैयारी, नवंबर में भारत आएंगी 25 प्रमुख साइप्रस कंपनियां

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत के समुद्री और जहाज निर्माण क्षेत्र में निवेश तथा तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए साइप्रस की लगभग 25 प्रमुख कंपनियां नवंबर में भारत का दौरा करेंगी। इन कंपनियों के प्रतिनिधि शिपिंग, शिप मैनेजमेंट, समुद्री प्रौद्योगिकी और उससे जुड़े क्षेत्रों में साझेदारी की संभावनाओं का आकलन करेंगे। यह जानकारी एक आधिकारिक बयान में दी गई।

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दक्षिण कोरिया के बुसान में दक्षिण कोरियाई समुद्री संस्थानों, जहाज निर्माण कंपनियों और साइप्रस के शिपिंग उपमंत्री मरीना हाजीमानोलिस के साथ कई महत्वपूर्ण बैठकें कीं। इन चर्चाओं का मुख्य फोकस भारत की बयती जहाज निर्माण महत्वाकांक्षाओं के लिए आवश्यक सप्लाई चेन, वित्त, प्रौद्योगिकी और बाजारों को मजबूत करना था।

बैठकों के दौरान जहाज निर्माण निवेश, समुद्री उपकरण विनिर्माण, समुद्री वित्तपोषण, बंदरगाह विकास, शिपिंग, हरित प्रौद्योगिकी और टिकाऊ जहाज पुनर्चक्रण (शिप रीसाइक्लिंग) जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। साइप्रस ने भारतीय शिप रीसाइक्लिंग यार्डों को यूरोपीय संघ से मान्यता दिलाने के भारत के प्रयासों का भी समर्थन किया।

भारत और दक्षिण कोरिया के बीच एलपीजी तथा एलएनजी कार्गो टैंक, क्रायोजेनिक संरचनाओं और बड़े जहाज ब्लॉक्स के निर्माण में साझेदारी की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।



सोनोवाल ने दक्षिण कोरियाई समुद्री वित्तीय संस्थानों के सामने मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड (एमडीएफ) और सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन (एसएमएफसी) से जुड़े अवसरों को भी प्रस्तुत किया।

सरकारी बयान के अनुसार, दक्षिण कोरिया की एक प्रमुख शिपिंग कंपनी ने भारत में जहाजों की भारतीय ध्वज के तहत रजिस्ट्री, भारत में कंटेनर निर्माण और आगामी वधावन पोर्ट परियोजना में निवेश की रुचि दिखाई है। साइप्रस की शिपिंग उपमंत्री मरीना हाजीमानोलिस के साथ द्विपक्षीय बैठक में शिपिंग, जहाज निर्माण, समुद्री निवेश, नाविकों के कल्याण और समुद्री सेवाओं पर चर्चा हुई। इसी दौरान उन्होंने जानकारी दी कि साइप्रस की 25 अग्रणी कंपनियां नवंबर में भारत आकर संभावित व्यावसायिक साझेदारियों पर विचार करेंगी।

नई दिल्ली में 'तंबाकू मुक्त युवा अभियान 4.0' की शुरुआत

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने आज नई दिल्ली में 'तंबाकू मुक्त युवा अभियान 4.0' की शुरुआत की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा यह 60 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान युवाओं को तंबाकू के सेवन से रोकने, उन्हें तंबाकू छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने, तंबाकू नियंत्रण कानूनों को सख्ती से लागू करने और पूरे देश में तंबाकू–मुक्त माहौल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस अवसर पर बोलते हुए श्री जाधव ने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं को तंबाकू के सेवन से दूर रखना है, जिससे वे देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत के एक विकसित राष्ट्र बनने के सपने को पूरा करने के लिए युवाओं का स्वस्थ और खुशहाल होना बहुत जरूरी है। श्री जाधव ने बताया कि इस अभियान के पिछले तीन चरणों के दौरान 5 लाख 80 हजार से अधिक शिक्षण संस्थानों और 73 हजार गांवों को 'तंबाकू–मुक्त' घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि तंबाकू के हानिकारक प्रभाव केवल इसका सेवन करने वालों तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि उनके आसपास के लोग भी इससे प्रभावित होते हैं।

इतिहास के पन्नों में 29 अक्टूबर

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर (हि.स.)।

1709 – इंग्लैंड तथा नीदरलैंड ने फ्रांस विरोधी संधि पर हस्ताक्षर किए।
1794 – फ्रांसिसी सेना ने दक्षिण पूर्वी नीदरलैंड के वेनलो पर कब्जा किया।
1851 – बंगाल में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना।
1859 – स्पेन ने अफ्रीकी देश मोरक्को के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।
1864 – यूनान ने नया संविधान अंगीकार किया।
1913 – मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर में बाढ़ से हजारों लोग मारे गये।
1920 – पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के प्रयासों से जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना।
1923 – ऑटोमन साम्राज्य का अंत होने की घोषणा के साथ ही तुर्की में संसदीय लोकतंत्र मजबूत होने लगा और आज ही के दिन देश गणराज्य बना।
1924 – ब्रिटेन में लेबर पार्टी की संसदीय चुनाव में हार।
1929 – अमेरिकी शेयर बाजार के करीब एक करोड़ 60 लाख शेयर की बिकवाली के चलते इसे 'ब्लैक ट्यूजडे' कहा गया।
1942 – नाजियों ने बेलारूस के पिनस्क में 16 हजार यहूदियों की हत्या की।
1945 – विश्व में पहला बॉल पोइंट पेन बाज़ार में आया।
1947 – बेल्जियम, लक्जमबर्ग तथा नीदरलैंड ने बेनेलक्स संघ बनाया।
1956 – इजराइल की सेना ने स्वेज नहर इलाके पर कब्जा करने के लिए सिनाई प्रांत में मिस्र पर हमला किया।
1958 – अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया।
1975–स्पेन से जनरल फ्रैंको के 35 साल पुराने शासन का अंत।
युवराज जुआन कार्लोस ने अस्थायी तौर पर सत्ता संभाली।
1990–अफ्रीकी देश अल्जीरिया में भूकंप से 30 लोग मारे गये।
1994 – न्यूयार्क में अमेरिकी भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय का शुभारंभ।
1995 – जनमत संग्रह में कनाडा क्यूबेक प्रान्त की जनता ने कनाडा के साथ रहने का निर्णय लिया।
1997 – पाकिस्तान द्वारा अंतरराष्ट्रीय रासायनिक हथियार संधि की पुष्टि।
1999 – उड़ीसा में चक्रवात ने ली हजारों की जान।
2000 – आइसलैंड के राष्ट्रपति ओलोफर रेगनर ग्रिमसन सात दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे।
2001 – पाकिस्तान में कट्टरपंथी कबाइलियों ने पाक अधिकृत कश्मीर के चिलास क़स्बे की हवाई पट्टी, जेल और पेट्रोल पम्पों पर कब्ज़ा किया।
2004 – त्रिनिदाद एवं टोबैगो के राष्ट्रपति मेक्सवेल रिचर्डस ने नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के साथ वार्ता की।
2005 – 'आयल फ़ार फूड प्रोग्राम' विषयक बोल्कर रिपोर्ट में भारत के विदेश मंत्री नटवर सिंह पर उंगली उठाई गयी।
2005 – दिल्ली में दीपावली के दो दिन पहले व्यस्त इलाकों में सिलसिलेवार बम धमाकों में 62 लोगों की मौत।
2008 – असोम में हुए बम विस्फोट में 69 लोग मारे गये तथा 350 लोग घायल हुए।
2012 – अमेरिका के पूर्वी तट पर सैंडी तूफान के कारण 286 लोगों की मौत।
2012– ऑस्ट्रेलिया के स्कूलों में हिंदी और अन्य प्रमुख एशियाई भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। भारत और अन्य एशियाई देशों से संबंध मजबूत बनाने के लिए यह रणनीति तय की गई है।
2012– शीर्ष भारतीय खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने फिर अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए इंग्लैंड के मौजूदा चैंपियन और स्थानीय प्रबल दावेदार माइक रसेल को हराकर सातवां वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप ख़िताब अपने नाम किया।
2015 – चीन ने एक बच्चे की नीति को खत्म करने की घोषणा की।

सत्र 2026–27 हेतु सामान्य पूल के अंतर्गत सरकारी आवासों के आबंटन के लिए वरिष्ठता सूची (प्रकार–वार/श्रेणी–वार) पर दावे/आपत्तियाँ आमंत्रित करने के संबंध में सूचना

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, सचिवालय के आवास एवं संपदा अनुभाग द्वारा प्रशासन के परिपत्र संख्या 1-167/2021/H&E/Vol-VII दिनांक 27.05.2026 के माध्यम से सत्र 2026–27 हेतु सामान्य पूल के अंतर्गत सरकारी आवासों के आवंटन के लिए नए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (DDOs)/कार्यालयाध्यक्षों (HOOs) द्वारा विधिवत सत्यापित सरकारी कर्मचारियों से प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर, प्रकार–वार/श्रेणी–वार अंतिम वरिष्ठता सूची तैयार की गई है।

उक्त सूची आवेदकों की जानकारी हेतु AAGA पोर्टल के होमपेज पर '*Seniority List (General Pool)" शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है। पोर्टल का वेब पता https://aaga.andamannicobar.gov.in है। आवेदक अपनी वरिष्ठता से संबंधित दावे/आपत्तियाँ, यदि कोई हों, तो अपने संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO)/कार्यालयाध्यक्ष (HOO) के माध्यम से सहायक सचिव (आवास एवं संपदा), सचिवालय को दिनांक 04.11.2026 को अपराह्न 5.00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समय–सीमा के भीतर कोई दावा/आपत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में उक्त अंतिम वरिष्ठता सूची को अंतिम वरिष्ठता सूची माना जाएगा।

सहायक सचिव (आवास एवं संपदा)
F.No. 1-167/2021/H&E/Vol-VII

आई.सी.एम.आर.–क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पोस्ट बैग नंबर 13, डॉलीगंज, श्री विजय पुरम – 744103,
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

रिक्ति सूचना

सं. 1-18/Appt/YP-II/HT/RMRC/SVP/365, दिनांक 27/10/2026

आई.सी.एम.आर.–क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, श्री विजय पुरम में 23 नवंबर 2026 को सुबह 9.00 बजे से भारतीय नागरिकों के लिए एक 'वॉक–इन इंटरव्यू' (walk-in interview) आयोजित किया जा रहा है। यह भर्ती "**यंग प्रोफेशनल–।। (प्रशासन) हिंदी अनुवादक**" **(YOUNG PROFESSIONAL-II (ADMINISTRATION) HINDI TRANSLATOR)** के पद के लिए है, जो पूरी तरह से अस्थायी आधार पर और शुरुआती तौर पर एक वर्ष की अवधि के लिए होगी। इसका विवरण नीचे दिया गया है :–

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	समेकित वेतन
1	**यंग प्रोफेशनल–।। (प्रशासन) हिंदी अनुवादक**	01 (एक)	42,000/– रुपये प्रति माह
	आयु – अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष (नियमों के अनुसार छूट दी जा सकती है) **शैक्षिक योग्यता** :– हिंदी में मास्टर डिग्री, जिसमें अंग्रेजी एक अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में रही हो; या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री, जिसमें हिंदी एक अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में रही हो; अथवा किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री, बशर्ते उम्मीदवार ने डिग्री स्तर पर हिंदी या अंग्रेजी में से किसी एक को अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ा हो। और अनुवाद (हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी) में कोई मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या प्रमाण पत्र; अथवा केंद्र/राज्य सरकार के कार्यालयों या भारत सरकार के उपक्रमों में अनुवाद कार्य (हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी) का दो वर्ष का अनुभव। **वांछनीय योग्यता** :– उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास अनुवाद में डिप्लोमा हो, जिन्हें कंप्यूटर पर हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग आती हो, जिन्हें MS Office का बुनियादी ज्ञान हो, और जिनके पास अनुवाद कार्य के क्षेत्र में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव हो।		

विस्तृत विज्ञापन के लिए, कृपया ICMR-RMRC की वेबसाइट https://www.icmr.nic.in और www.rmrc.res.in देखें।

निदेशक

शपथ पत्र

मैं, फरीज़ा युसुफ, पिता युसुफ, माता जुबैदा बीबी, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी अबरडीन विल्लेज, श्री विजय पुरम, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, शपथपूर्वक घोषणा करती हूँ कि :

1. मेरे पुराने पासपोर्ट में मेरा नाम "Fareeza Yusuf" दर्ज है।
2. मेरे सभी अन्य दस्तावेजों एवं आधिकारिक अभिश्लेखों में मेरा सही नाम "Fariza Yusuf" है।
3. "Fareeza Yusuf" और "Fariza Yusuf" दोनों नाम एक ही व्यक्ति अर्थात मेरे ही हैं।
4. मेरे पासपोर्ट में नाम की वर्तनी में अंतर अनजाने में हुई गलती के कारण है।
5. अतः संबंधित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से अनुरोध है कि मेरे पासपोर्ट में नाम "Fareeza Yusuf" से बदलकर "Fariza Yusuf" किया जाए।
6. यह शपथ पत्र पासपोर्ट में नाम सुधार एवं अन्य आधिकारिक कार्यों के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।
7. उपरोक्त सभी कथन मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं तथा कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है।

शपथकर्ता

एनटीपीसी NTPC **एन टी पी सी लिमिटेड**
(भारत सरकार का उद्यम)

विज्ञापन संख्याः 15/26

एनटीपीसी लिमिटेड 91 गीगावॉट से अधिक की स्थापित क्षमता के साथ भारत का सबसे बड़ा विद्युत समूह है। हमारे देश की विकास संबंधी चुनौतियों के अनुरूप, एनटीपीसी ने वर्ष 2032 तक 149 गीगावॉट की कुल स्थापित क्षमता प्राप्त करने की महत्वाकांक्षी योजना है।
अपनी महत्वाकांक्षी विकास योजनाओं को गति देने के लिए, एनटीपीसी को **ग्रेट निकोबार द्वीप (जीएनआई) में गैस इंजन आधारित विद्युत परियोजना के लिए निश्चित अवधि के आधार पर अनुभवी पेशेवरों** की आवश्यकता है। विवरण निम्नानुसार हैः

पद का नाम	रिक्तियाँ
कार्यपालक (सिविल)	02
कार्यपालक (इलेक्ट्रिकल)	02
कार्यपालक (मेकेनिकल)	02

दृच्छुक और पात्र उम्मीदवार विस्तृत पात्रता मानदंड, योग्यता मानदंड, अनुभव मानदंड, विज्ञापन का पूरा विवरण देखने और आवेदन करने के लिए हमारी वेबसाइट **careers.ntpc.co.in** पर लॉग इन करें। आवेदन का केवल ऑनलाइन माध्यम ही स्वीकार किया जाएगा। **ऑनलाइन आवेदन पोर्टल 30.10.2026 से 13.11.2026 (शाम 06 बजे तक) तक खुला रहेगा।** कोई भी पूरक परिशिष्ट/शुद्धिपत्र/अपडेट केवल हमारी वेबसाइट पर ही प्रकाशित किया जाएगा।

विद्युत क्षेत्र में अग्रणी

भारत–यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर इसी साल हस्ताक्षर होने की उम्मीद

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर (हि.स.)। उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति श्री सीपी राधाकृष्णन ने बुधवार को उम्मीद जताई कि भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते पर इस साल हस्ताक्षर हो जाएंगे। उन्होंने इसे 'सभी समझौतों की जननी' करार देते हुए समझौते को अंतिम रूप देने में यूरोपीय संसद से आवश्यक सहयोग मांगा।

श्री राधाकृष्णन ने संसद भवन में यूरोपीय संसद की विदेश मामलों की समिति (एएफईटी) के अध्यक्ष डेविड मैकलिस्टर के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और यूरोपीय संघ के संबंधों में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने दोनों पक्षों के नेतृत्व को इन संबंधों को आगे बढ़ाने का श्रेय दिया।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों और खुले बाजार वाली अर्थव्यवस्थाओं के रूप में भारत और यूरोपीय संघ विविधतापूर्ण एवं बहुलतावादी समाज हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के नेतृत्व में पूरे सरकारी तंत्र की भागीदारी के साथ हुए दौरे के बाद दोनों पक्षों के बीच संस्थागत संबंध मजबूत हुए हैं।

कैबिनेट ने 'प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना' को दी मंजूरी, 7,395 करोड़ रुपए की स्कीम से 2.55 लाख पंचायतों को मिलेगा फायदा



नई दिल्ली, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (पीएम वीजीएसवाई) को वर्ष 2026–27 से 2030–31 तक लागू करने के लिए मंजूरी दे दी है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) होगी, जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों को स्थानीय विकास और सुशासन का केंद्र बनाना है। विकसित भारत के विजन के अनुरूप तैयार की गई इस योजना के लिए कुल 7,395.55 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 4,869.48 करोड़ रुपए और राज्यों का हिस्सा 2,526.07 करोड़ रुपए होगा।

एक आधिकारिक बयान में कैबिनेट ने बताया कि इस योजना का सीधा लाभ देशभर की 2.55 लाख से अधिक पंचायतों और पारंपरिक स्थानीय निकायों से जुड़े लगभग 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों, पंचायत कर्मियों और अन्य हितधारकों को मिलेगा। इसके अलावा, जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से हर बार कम से कम 1 करोड़ नागरिकों तक पहुंच बनाई जाएगी।

प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है। इसके तहत हर वर्ष ईग्रामस्वराज पोर्टल पर लगभग 2.55 लाख समग्र ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (जीपीडीपी) तैयार की जाएंगी। इन योजनाओं में गांवों की जरूरतों, केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं तथा उपलब्ध संसाधनों को एक साथ जोड़कर भागीदारी आधारित विकास मॉडल तैयार किया जाएगा।

सरकार का कहना है कि इससे 'विकसित भारत' के राष्ट्रीय विजन को गांवों की जरूरतों और आकांक्षाओं से सीधे जोड़ा जा सकेगा। पंचायतें केवल प्रशासनिक इकाई न रहकर स्थानीय विकास की वास्तविक धुरी बनेंगी। इस योजना के तहत ईग्रामस्वराज और अन्य ई–पंचायत प्रणालियों को और मजबूत किया जाएगा। एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सरकारी योजनाओं, लाभार्थियों, सामुदायिक परिसंपत्तियों और उपलब्ध संसाधनों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे पंचायतों को विकास में मौजूद कमियों की पहचान करने, स्थानीय जरूरतों को समझने और योजनाओं की निगरानी करने में मदद मिलेगी।

बयान में कहा गया है कि सरकार पंचायतों और नागरिकों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए पंचम नामक एआई–सक्षम बहुभाषी संचार प्लेटफॉर्म का उपयोग करेगी, जो 17 भारतीय भाषाओं में काम करेगा और लोगों को सरल भाषा में सरकारी योजनाओं और राष्ट्रीय पहलों की जानकारी देगा।

योजना के तहत हर वर्ष करीब 32 लाख जनप्रतिनिधियों और पंचायत अधिकारियों को प्रशिक्षण और डिजिटल सहायता प्रदान की जाएगी। उन्हें विकास योजनाएं बनाने, संसाधन प्रबंधन, नागरिकों से संवाद और स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को हासिल करने के लिए तैयार किया जाएगा।

'निष्पक्ष खेल' बनेगा शिक्षा का हिस्सा, खेल और शिक्षा मंत्रालय ने यूनेस्को संग मिलकर किया समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर



नई दिल्ली, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। युवा मामले और खेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और यूनेस्को ने पूरे भारत की कक्षाओं में 'स्पोर्ट्स वैल्यूज इन एवरी क्लासरूम टूलकिट' (हर कक्षा में खेल मूल्य टूलकिट) के माध्यम से 'निष्पक्ष खेल' मूल्यों को शामिल करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों के बीच ईमानदारी, निष्पक्षता और सम्मान की भावना को बयावा देना है।

यह समझौता बुधवार को नई दिल्ली में नेशनल एंटी–डोपिंग एजेंसी इंडिया के 'क्लीन स्पोर्ट कॉन्क्लेव' के दौरान किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी और दक्षिण एशिया के लिए यूनेस्को के क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक टिम कर्टिस मौजूद थे।

इस टूलकिट में 13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध शैक्षिक संसाधनों और वीडियो मॉड्यूल का उपयोग किया जाएगा, ताकि देश भर के छात्रों तक पहुंचा जा सके। यह पहल 'खेलो भारत नीति 2025' में खेल और शिक्षा को एक साथ जोड़ने के लक्ष्य के अनुरूप है और इसका उद्देश्य बच्चों में कम उम्र से ही 'निष्पक्ष खेल' के प्रति जागरूकता पैदा करना है।

खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, "खेल में उत्कृष्टता और खेल की ईमानदारी साथ–साथ चलनी चाहिए। खेल में सफलता के लिए प्रतिभा, अनुशासन और कड़ी मेहनत जरूरी है, लेकिन ईमानदारी, निष्पक्षता और विश्वसनीयता भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं।" उन्होंने भारत की बयती खेल महत्वाकांक्षाओं के साथ–साथ 'निष्पक्ष खेल' के प्रति जागरूकता को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

खेल मंत्री ने एशियाई खेलों और एशियाई पैरा खेलों में भारत के चौथे स्थान पर रहने का जिक्र करते हुए इसे देश की बयती खेल ताकत का संकेत बताया। इसके साथ ही, उन्होंने चेतावनी दी कि डोपिंग अभी भी एक गंभीर चिंता का विषय है, जिसके लिए शिक्षा, रोकथाम, परीक्षण और नियमों के सख्ती से पालन की दिशा में निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा, "2025–26 के दौरान, नेशनल एंटी–डोपिंग एजेंसी (नाडा) इंडिया ने 7,000 से अधिक परीक्षण किए और 350 से अधिक शिक्षा एवं जागरूकता सत्र आयोजित किए, जिनमें 27,000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। गांधीनगर स्थित नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी और हैदराबाद स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में सप्लीमेंट टेस्टिंग की सुविधाएं, अनजाने में होने वाली डोपिंग के मामलों को रोकने में मदद करेंगी। इसके साथ ही, वैश्विक मानकों के अनुरूप नाडा के भीतर जांच प्रक्रियाओं को मजबूत किया जाएगा। नेशनल एंटी–डोपिंग एक्ट इस साल लागू हो गया है और सरकार डोपिंग से जुड़ी गतिविधियों को अपराध की श्रेणी में लाने के लिए संसद में प्रावधान लाने की तैयारी कर रही है।"

आईसीसी रैंकिंगः दुनिया के नंबर एक टी20 बल्लेबाज बने अभिषेक शर्मा

दुबई, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में धमाकेदार शतकीय पारी खेलने का इनाम भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को आईसीसी की ताजा टी20 रैंकिंग में मिला है। अभिषेक दुनिया के नंबर एक टी20 बल्लेबाज बन गए हैं।

अभिषेक ने ईशान किशन को पीछे छोड़ते हुए नंबर एक की पोजीशन हासिल की है। वहीं, साउथ अफ्रीका के मार्को जानसेन टेस्ट क्रिकेट में विश्व के नंबर एक गेंदबाज और ऑलराउंडर बन गए हैं। गकेबेरहा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका की जीत में शानदार प्रदर्शन करने के बाद, जानसेन ने अपने करियर में पहली बार इन दोनों श्रेणियों में टॉप रैंकिंग हासिल की है। इस बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने 85 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 5 विकेट लेकर मैच का रुख ही बदल दिया था।

26 वर्षीय जानसेन टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में 13 स्थान की छलांग लगाकर 56वें नंबर पर पहुंच गए हैं। टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में वह 5 स्थान ऊपर चढ़कर ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क को पीछे छोड़ते हुए टॉप पर आ गए हैं, और टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में एक स्थान ऊपर उठकर भारत के रवींद्र जडेजा को पीछे छोड़ते हुए नंबर वन बन गए हैं।

जडेजा पिछले 4 साल से भी ज्यादा समय तक टेस्ट ऑलराउंडरों की सूची में टॉप पर बने हुए थे। जानसेन ने यह छलांग ऐसे समय में लगाई है, जब साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने हाल ही में उन्हें 'दुनिया का सबसे बेहतरीन क्रिकेटर' बताया था। वहीं, मंगलवार को वेलिंगटन में सीरीज के तीसरे मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ



तूफानी शतक लगाने के बाद अभिषेक टी20 बैटिंग रैंकिंग में फिर से टॉप पर आ गए हैं।

बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने सिर्फ 35 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और कुल 38 गेंदों में 113 रन बनाए। उनकी इस पारी की बदौलत भारत ने 6 विकेट से जीत दर्ज की और सीरीज अपने नाम कर ली। उनकी इस पारी ने उन्हें अपने साथी खिलाड़ी ईशान किशन को पीछे छोड़कर टॉप स्थान पर पहुंचने में मदद की।

इससे पहले, इस साल जुलाई में आयरलैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद ईशान किशन ने अभिषेक से नंबर एक की पोजीशन छीन ली थी। अभिषेक पहली बार जुलाई 2025 में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को पीछे छोड़कर टी20 इंटरनेशनल बैटिंग रैंकिंग में टॉप पर पहुंचे थे। साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा को ताजा रैंकिंग में बड़ा फायदा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुने जाने के बाद वह टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में चार स्थान ऊपर चयकर दूसरे नंबर पर आ गए हैं।

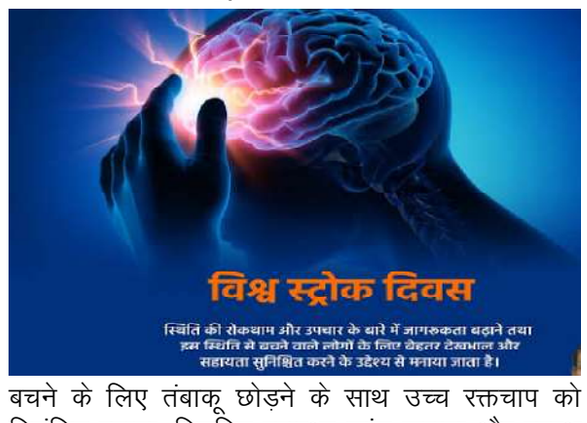
विश्व स्ट्रोक दिवसः स्ट्रोक से बचना है तो तंबाकू से बनाएं दूरी

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर। तंबाकू का सेवन न केवल फेफड़ों बल्कि दिल और दिमाग की रक्त वाहिकाओं को भी नुकसान पहुंचाता है। इससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। विश्व स्ट्रोक दिवस पर विशेषज्ञों ने लोगों को तंबाकू से दूर रहने और इसकी लत छोड़ने के लिए समय पर मदद लेने की सलाह दी है। विशेषज्ञों के अनुसार, देश में हर साल करीब 13.5 लाख मौतें तंबाकू के सेवन से जुड़ी होती हैं। ऐसे में केवल जागरूकता फैलाना काफी नहीं है, बल्कि लोगों को तंबाकू छोड़ने के लिए उचित उपचार और लगातार सहायता देना भी जरूरी है।

ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के आंकड़ों के 2024 के विश्लेषण के अनुसार, भारत में स्ट्रोक से होने वाली मौतों में 12 फीसदी का योगदान तंबाकू के सेवन का था। वहीं, बढ़े हुए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप के ऊपरी स्तर का योगदान 56 फीसदी था। इससे साफ है कि स्ट्रोक से बचाव के लिए तंबाकू छोड़ने के साथ ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखना भी जरूरी है।

न्यूरोसर्जरी और न्यूरोसाइंसेज डॉ. यशपाल सिंह बुंडेला के अनुसार, निकोटीन की लत के कारण तंबाकू छोड़ना मुश्किल हो सकता है। कई लोग इसके नुकसान जानते हुए भी इसका सेवन जारी रखते हैं। ऐसे लोगों को चिकित्सकीय सलाह और लगातार मदद की जरूरत होती है। निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी जैसे उपचार भी डॉक्टर की सलाह पर मददगार हो सकते हैं। उनके अनुसार, देश में तंबाकू का इस्तेमाल सिगरेट और बीड़ी के अलावा खैनी, गुटखा और जर्दा जैसे उत्पादों के रूप में भी किया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार, निकोटीन की लत लग सकती है, जबकि तंबाकू के जहरीले रसायन दिल और रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए तंबाकू के सभी रूपों से बचना जरूरी है।

रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के डॉ. विकास मित्तल के अनुसार, तंबाकू नियंत्रण के लिए वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित उपाय अपनाने चाहिए। उन्होंने कहा कि स्ट्रोक से



बचने के लिए तंबाकू छोड़ने के साथ उच्च रक्तचाप को नियंत्रित रखना, नियमित स्वास्थ्य जांच कराना और स्वस्थ जीवनशैली अपनाना जरूरी है। युवाओं को तंबाकू की लत से बचाना और इसकी लत से जूझ रहे लोगों को उपचार उपलब्ध कराना भी अहम है। समय रहते जोखिम कारकों पर ध्यान देकर स्ट्रोक और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम करने में मदद मिल सकती है।

भारत–नेपाल की सीमा सुरक्षा बलों की वार्षिक बैठक शुरू

भारत और नेपाल की सीमा सुरक्षा बलों ने बुधवार को काठमांडू में अपनी 10वीं वार्षिक समन्वय बैठक शुरू की है। इसका मुख्य उद्देश्य सीमा सुरक्षा को मजबूत करना, सीमा पार अपराधों को रोकना और वास्तविक समय में खुफिया जानकारी साझा करने में सुधार करना है। तीन दिवसीय इस बैठक में दोनों देशों की प्रमुख सुरक्षा और सरकारी एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के महानिदेशक संजय सिंघल कर रहे हैं और नेपाल के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सशस्त्र पुलिस बल (एपीएफ) के महानिरीक्षक नारायण दत्ता पौडेल कर रहे हैं। बैठक में भारत के गृह और विदेश मंत्रालयों, काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास तथा नेपाल के गृह और विदेश मंत्रालयों, नेपाल पुलिस, राष्ट्रीय जांच विभाग और सर्वेक्षण विभाग के प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं।